

प्रेषक,

मनीषा पंवार,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त नियंत्रक,

कुमाऊ विश्वविद्यालय,

नैनीताल ।

शिक्षा अनुभाग-6 (उच्च शिक्षा)

देहरादून

दिनांक: 21 अक्टूबर, 2013

विषय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 के आयोजनेत्तर पक्ष (Non-Plan) की मानक मद-20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता में धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: केयू/लेखा/बजट2013-14/550 दिनांक: 05.7.2013 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसमें वर्तमान वित्तीय वर्ष के आयोजनेत्तर पक्ष के मद-20 में विविध कार्यों के प्रयोजनार्थ धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु आयोजनेत्तर पक्ष (Non-Plan) में मानक मद-20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता आदि अबचनबद्ध मदों में प्राविधानित धनराशि ₹ 45000 हजार (अर्थात् ₹ 4,50,00,000/- चार करोड़ पचास लाख मात्र) को वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 284/XXVII(1)/2013 दिनांक: 30.3.2013 में दिए गए दिशा-निर्देशों एवं निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृत करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि लाख में)

क्र.सं.	व्यय की मद	विश्वविद्यालय द्वारा माँगी गई धनराशि	प्राविधानित धनराशि के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि
1.	मानदेय/यात्रा/दूरभाष/वाहनों पर व्यय/कार्यालय व्यय	146.50	140.00
2.	परीक्षा संचालन पर व्यय	312.00	चूँकि उक्त कार्यों हेतु छात्रों से परीक्षा शुल्क लिया जाता है, इस कारण इस मद में धनराशि अवमुक्त नहीं की जा रही है।
3.	मुद्रण गोपनीय मुद्रण	100.00	90.00
4.	उपकरण/फर्नीचर/साज सज्जा/कम्प्यूटर कय आदि	77.50	68.00
5.	छात्रवृत्ति/औषधालय आदि	48.35	40.00
6.	विविध आ0व्यय/अन्य व्यय/ बीमा प्रीमियम	32.50	05.00
7.	सम्परीक्षा शुल्क	19.00	12.00
8.	प्रयोगशाला/पुस्तकालय/वार्षिक अनुरक्षण	112.50	95.00
	कुल-		450.00 (चार करोड़ पचास लाख मात्र)

- (1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय केवल अबचनबद्ध मदों की आय-व्ययक के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किशतों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के आधार ही किया जाएगा, तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी। उक्त स्वीकृत धनराशि के बिल जिला शिक्षा अधिकारी, नैनीताल द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए जाएंगे।
- (2) विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी द्वारा उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जबकि गत वित्तीय वर्ष/वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार उपभोग कर लिया गया हो तथा कोई भी धनराशि अवशेष न हो। धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार ही किया जाएगा।
- (3) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008, तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए। उक्त मद में व्यय करने के उपरांत यदि धनराशि अवशेष रह जाती है तो प्रशासकीय विभाग को इसकी सूचना अनिवार्य रूप से दी जाय ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।
- (4) व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय-समय पर वित्त विभाग के निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इस संबंध में वेतन मदों के अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्य योजना बना ली जाय। तदनुसार विशेषकर आयोजनेत्तर पक्ष में बचत करने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर बचत किया जाना सुनिश्चित करें।
- (5) नए पदों के सृजन/ढ़ावें, नई नीति निर्धारण अथवा वर्तमान नीति में संशोधन, करों/यूजर्स चार्ज में संशोधन, निधियों का गठन, अनुदान राशि में संशोधन, नियमावलियों आदि सभी प्रकरण शासन को भेजे जाय, ताकि वित्त विभाग के परामर्श से अनुमोदन दिया जा सके।
- (6) विभिन्न मदों में व्यय भार/देयता सृजित होने पर यथाशीघ्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जाएगी एवं कोई भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जाएगा क्योंकि उससे मासिक आधार पर व्यय की भ्रामक सूचना परिलक्षित होती है। इस संबंध में समस्त वित्तीय नियमों, विनियमों एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 284/XXVII(1)/2013 दिनांक: 30.3.2013 में दिए गए दिशा-निर्देशों का भी पूर्णतः अनुपालन किया जाये।
- (7) स्वीकृत की जा रही धनराशि को पूर्वोक्त तालिका में वर्णित मदों में ही व्यय किया जाय। परीक्षा संचालन हेतु धनराशि स्वीकृत नहीं की जा रही है। परीक्षा संचालन से संबंधित कार्यों हेतु विश्वविद्यालय स्वयं के स्रोतों से धनराशि की व्यवस्था कर सकता है। किसी भी दशा में एक मद की धनराशि दूसरे मद में व्यय न की जाये अन्यथा की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी का पूर्णतः उत्तरदायित्व होगा। जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किए जाय, उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या/मद का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जाय।
- (8) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रियानुसार कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित बजट की सीमा तक प्रपत्र बी0एम0-08 पर व्यय विवरण शासन के प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को माह की अगली 05 तारीक तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।



(9) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि (वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के पैरा-162) समस्त आहरित अग्रिमों का समायोजन आहरण-वितरण अधिकारियों द्वारा 30 दिनों के अन्दर कर दिया जाय तथा डीटेल्ड कन्टीजेन्ट (डी0सी0) बिल महालेखाकार को भेज दिए जाय। विभिन्न अग्रिमों का आहरण अधिकारों के प्रतिनिधायन 2010 में दी गई सीमाओं के अनुसार ही किया जाय।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 284/XXVII(1)/2013 दिनांक: 30.3.2013 में निहित प्राविधानुसार तथा www.cts.uk.gov.in से साफ्टवेयर के माध्यम से निर्गत विशिष्ट एलॉटमेंट आई0डी0संख्या-11310110870 (प्रति संलग्न) द्वारा निर्गत किए जा रहे हैं।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु लेखानुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-102-विश्वविद्यालयों को सहायता-आयोजनेत्तर-03-कुमाऊ विश्वविद्यालय-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता की सुसंगत इकाई के नामें डाला जायेगा।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या/343/XXIV(6)/2013/12(4)12 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
3. कोषाधिकारी, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, नैनीताल।
5. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, नैनीताल।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, उत्तराखण्ड।
8. वित्त अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
9. बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शमाम सिंह)
अनुसचिव।